तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

Outstanding duty drawback claims of Delhi exporters

2713. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that customs procedure has held up duty drawback claims of atleast one thousand exporters of Delhi;

(b) if so, the total amount held up, and

(c) whether Government propose to take further steps to simplify the procedure and if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) No duty drawback claims have been unduly he!d-up in processing due to customs procedure. Duty drawback claims are settled by issue of cheques on Punjab National Bank in the names of the exporters. However, due to non-supply of cheque books, during the month of June, 1994, some pendency of duty drawback payments had arisen during that month which has since been cleared.

(b) Non applicable at present in view of (a) above.

(c) To further expedite the disbursal of duty drawback, the procedures are constantly reviewed so as to steamline the settlement of drawback claims.

फोर्ड फाउन्डेशन की गतिविधियां

2714. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फोर्ड फाउन्डेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन की भारत में क्या-क्या गतिविधियां हैं;

(ख) इनकी गतिविधियों पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है;

(ग) क्या सरकार को इनकी गतिविधियों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) फोर्ड फाउन्डेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन शैक्षिक, वैज्ञानिक, साक्षरता और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए लाभ अर्जित न करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों अनुसंधान संस्थाओं और कुछ सरकारी अभिकरणों को वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। ये संगठन लोगों की विदेश में उनके प्रशिक्षण/अध्ययन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) वित्तीय अनुदानग्राही को सहायता प्रदान करने से पूर्व फोर्ड फाउंडेशन और रोकफेलर फाउन्डेशन को प्रत्येक अनुदान से संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और केवल उपयुक्त मामलों में ही सहमति दी जाती है। इन संगठनों द्वारा प्रदत्त अनुदान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत भी विनियमित होता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए सवाल पैदा नहीं होते।

Financing by 1FCI

2715. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether IFCI is financing partially or fully various industrial units in Andhra Pradesh;

(b) if so, the sanctions accorded for financing industries in Andhra Pradesh in 1993-94 and in the current year upto 30th June, 1994;

(c) the names of such units and amounts, respectively;

(d) whether various auditing agencies have pointed out that late and delayed disbursals are the primary cause of non-profitability of IFCI; and

(e) if so, the details of such reports'?